नई दिल्ली, सोमवार, 31 मई, 2021
संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

मन की बात जारी रहेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बदस्तूर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात की। उन्होंने एक बार फिर देश को बता दिया कि जनता चाहे जिस हाल में रहे, वे अपने मन की बात कहना और मनमानी करना नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो इस वक्त देश जिन हालात से गुजर रहा है, उनमें कई सारे मुद्दों पर जनता देश का मुखिया होने के नाते मोदीजी से उनका पक्ष, उनकी राय जानना चाहती है। लेकिन वो तो जन की बात हो जाती, जबकि मोदीजी का कार्यक्रम मन की बात है, उसका जनसरोकारों से क्या वास्ता। हालांकि इस कार्यक्रम के प्रस्तोताओं की कोशिश यही रहती है कि इसे जनता के कार्यक्रम की तरह पेश किया जाए, लेकिन इस कोशिश की परतें कहीं न कहीं से उखड़ ही जाती हैं और सच सामने आ जाता है, जैसे गंगा किनारे दफ्न शवों के ऊपर से कफन हट गए, तो सरकारी व्यवस्था की सच्चाई सामने आ गई।

बहरहाल, 30 मई को मोदीजी के मन की बात के दौरान संयोग ये बना कि हाल ही में उनके प्रधानमंत्रित्व काल के 7 साल पूरे हुए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस खास मौके का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि आज 30 मई को हम मन की बात कर रहे हैं और संयोग से ये सरकार के 7 साल पूरे होने का भी समय है। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। देश की सेवा में हम सभी ने हर क्षण समर्पित भाव से काम किया। इन 7 वर्षों में ही देश के अनेक पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द्र से सुलझाए गए हैं। पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक शांति और विकास का एक नया भरोसा जगा है। इन 7 सालों में हमने सरकार और जनता से ज़्यादा एक देश के रूप में काम किया, टीम इंडिया के रूप में काम किया।

जिस किसी ने ये स्क्रिप्ट लिखी है, उसकी कल्पनाशक्ति की दाद देनी चाहिए। पिछले सात सालों की जो उपलब्धि मोदीजी बता रहे हैं, उसके बरक्स अगर आस-पास नजर दौड़ाई जाए, तो सात सालों की हासिल समझ आ जाएगा। देश में बेरोजगारी, गरीबों की संख्या और कुछ उद्योगपतियों की दौलत में एक साथ बढ़ोतरी हुई है, क्या इसे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहा जा सकता है। सरकार का खजाना खाली हुआ है, निजीकरण को बढ़ावा देकर राजकोषीय घाटा पूरा करने में सरकार का ध्यान है और कहा जा रहा है कि हमने समर्पित भाव से काम किया। और जिन पुराने विवादों को शांति से सुलझाने का दावा किया गया, उनकी हकीकत भी सब जानते हैं, बस इस वक्त माहौल ऐसा बना दिया गया है कि सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ खुलकर बोलने का चलन खत्म सा होता जा रहा है। कश्मीर के लोगों से किए गए वादे को तोड़ते हुए कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया, उसे दो हिस्सों में बांटा गया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, वहां अब तक चुनाव नहीं हुए हैं, विपक्ष को वहां जाकर जमीनी हकीकत जानने से रोका गया, क्या इसे नया भरोसा जागना कहा जा सकता है। कोई भी टीम ऐसी तो नहीं होती, जहां कप्तान अपने मन से फैसले ले, उन्हें सब पर थोप दे। जबकि मोदीजी ने लगातार एकतरफा फैसले ही लिए हैं। नोटबंदी, अनुच्छेद 370, सीएए, कृषि बिल ऐसे अनेक मसले हैं, जिन पर विपक्ष तो दूर, अपने सहयोगियों से भी मोदीजी ने चर्चा करना जरूरी नहीं समझा।

मन की बात में मोदीजी ने कोरोना को सौ सालों में सबसे बड़ी महामारी बताते हुए कहा कि हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर, नर्स और फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने खुद की चिंता छोड़कर दिन-रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। अच्छा है कि उन्हें डाक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की मेहनत नजर आई। लेकिन और अच्छा होता, अगर वे इसके साथ उन लोगों को भी दो-चार खरी-खरी सुना देते, जो इस वक्त लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐलोपैथी और डाक्टर्स के खिलाफ तमाम अनर्गल बातें करने के बाद रामदेव खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि किसी का बाप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। आज अगर मोदीजी अपने कार्यक्रम से इस चुनौती का जवाब दे देते, तो उनकी असल हिम्मत के दीदार जनता को हो जाते।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किसानों के रिकार्ड उत्पादन का भी जिक्र किया और कहा कि किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया, तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की है। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है। इस तरह उन्होंने अपनी पीठ भी थपथपा ली और नए कृषि कानूनों पर विरोध को बड़ी चतुराई से नजरंदाज कर दिया। वैसे प्रधानमंत्री देखें या न देखें, देश तो देख रहा है कि किसान पिछले छह महीनों से इन कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत हैं। वे अब सरकार से बातचीत की नयी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन मोदीजी ने जतला दिया कि उन्हें इन सब बातों की परवाह नहीं है। जनता जब तक विश्वगुरु, हिंदू राष्ट्र, मंदिर-मस्जिद, गाय और सूअर के नाम पर भावनाओं में बहकर वोट देती रहेगी, मन की बात इसी तरह जारी रहेगी।

सीढ़ी

मुझे एक सीढ़ी की तलाश है
सीढ़ी दीवार पर
चढ़ने के लिए नहीं
बल्कि नींव में उतरने के लिए
मैं किले को जीतना नहीं
उसे ध्वस्त कर देना चाहता हूं।

नरेश सक्सेना

सबसे अच्छा सबक विरोधी से ही मिलता है!

सात साल! क्या सबक है? किसी और के लिए नहीं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के लिए। क्या कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के इन सात सालों के शासन से कुछ सीखा?

कांग्रेसी सीखने में बहुत कमजोर हैं। कहेंगे हमें क्या सीखना? सही भी है। इन्होंने अपनी नेता इन्दिरा गांधी से नहीं सीखा तो किसी दूसरे से क्या सीखेंगे! मगर इन सात सालों में सीखने को बहुत कुछ है। खासतौर से राहुल गांधी के लिए कि सरकार कैसे चलाई जाती है। सबसे आवश्यक सबक। राहुल को इन सात सालों के नोट्स लेकर रखना चाहिए। इस शीर्षक के साथ कि दम के साथ सरकार कैसे चलाएं!

राहुल विपक्ष में बहुत दम से काम कर रहे हैं। खासतौर से इस कोरोना के समय जब सबने हथियार डाल दिए, केन्द्र सरकार ने भी, तब भी राहुल लगातार सक्रिय रहे। बोलते रहे। सरकार को चेतावनियां देते रहे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बी.वी. श्रीनिवास के माध्यम से बड़े पैमानों पर लोगों की मदद करवाते रहे। खुद भी चुपचाप करते रहे। अपने लिए आए रेमडेसिवियर के इंजेक्शन खबर मिलने पर प्रियंका के माध्यम से किसी जरूरतमंद पत्रकार के परिवार को पहुंचा दिए। यह भी नहीं देखा, पूछा कि वह पत्रकार उनके या कांग्रेस के खिलाफ क्या लिखता है। खुद कोरोना से ग्रस्त थे। डॉक्टर ने इमरजेन्सी के लिए मंगवाकर रखवाए थे। मगर राहुल ने कहा कि अभी तो जरूरत नहीं है। जब होगी तब देखेंगे।

सवा साल से यह कर रहे हैं। खासतौर से उस मीडिया की मदद जो उन्हें ही हर बात के लिए दोषी बताता है। यहां तक कि इस कोरोना से नहीं निपट पाने का दोष भी उन पर रखने में उसे कोई शर्म नहीं आती। राहुल न शिकायत करते हैं न अपने द्वारा की मदद किसी को बताते हैं। वह तो खुद मदद पाने वाला कह दे, जैसे अपनी पत्नी के लिए कहीं इंजेक्शन न पा पाने वाले उस बड़े और कई पार्टियों के लिए काम कर चुके पत्रकार ने कह दिया। या जैसे एक वीडियो सामने आ गया था, जिसमें पत्रकार खुद बहुत टूटी अवस्था में अपने और परिवार का कोरोना से बुरा हाल बताते हुए अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। तब राहुल ने फौरन खुद फोन किया और इलाज की तथा दूसरी सारी व्यवस्थाएं करवाईं। तब पता चला। क्योंकि जब वीडियो देखकर चिंतित हुए दूसरे पत्रकार साथियों ने फोन किए, तब पता चला कि मदद हो गई है। राहुल ने इंतजाम करवा दिया है।

यह सब ठीक है। उच्च मानवीय मूल्य हैं। जो राहुल के अपने गांधी नेहरु परिवार के संस्कारों से और कांग्रेस की पुरानी परंपराओं से मिले हैं। मगर मुख्य सवाल राजकाज करने का है। जब मौका मिले तो सरकार कैसे चलाना है? यूपीए की तरह मौका गंवाना नहीं है। यह मौका केवल अपने लिए या पार्टी के लिए नहीं होता मुख्यत: तो जनता की जिन्दगी बदलने के लिए होता है। उसे शिक्षित करने, जागरूक करने के लिए होता है। जिसमें खासतौर से यूपीए के दस साल बुरी तरह विफल रहे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की लाख कोशिशों के बावजूद कांग्रेस के मंत्रियों और उस दौरान रहे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने कोई बड़ा प्रगतिशील, जनउपयोगी काम नहीं किया। खुद सोनिया को इस तरह की योजनाएं लागू करने के लिए अपने ही मंत्रियों के अड़ंगे सहने पड़े। किसानों की कर्ज माफी, मनरेगा, महिला बिल सब सोनिया की योजनाएं थीं। और यूपीए में बैठे कांग्रेस के मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों का काम था इन योजनाओं के खिलाफ अफवाहों को बल देना। विपक्ष तो संभल कर बोलता था कि लाभान्वित होने वालों में गलत मैसेज न जाए। मगर कांग्रेस के यथास्थितिवादी और प्रतिक्रियावादी नेताओं को किस का डर था? सोनिया ने बोला था, महिला बिल पर कि मुझे मालूम है मेरी पार्टी के कई लोग ही विरोधी हैं। कांग्रेस इन दस सालों में बहुत काम कर सकती थी। मगर कांग्रेस के नेताओं को बुनियादी कामों में कोई रुचि नहीं थी। सोनिया ने दस साल में दस से ज्यादा बार कहा होगा कि मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी लोगों के पास जाएं, उनकी समस्याएं जानें, उनसे पूछ कर उनके लिए योजनाएं बनाएं। कार्यकर्ताओं से मिलें, उनसे फीडबैक लें। मगर क्या मजाल कि किसी ने सुना हो। हां, प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होते ही नागपुर संघ मुख्यालय जरूर पहुंच गए थे।

शकील अख्तर

> जाहिर है कि राहुल बिल्कुल अलग चीजें चाहेंगे। मगर जो भी चाहें, उन्हें कड़ाई से लागू करना होगा। पार्टी के अंदर और बाहर के विरोधियों की तरफ से उसी तरह बेपरवाह रहते हुए जैसे इन्दिरा गांधी रहती थीं और मोदी रह रहे हैं। सोनिया अन्ना और रामदेव के आंदोलनों की हकीकत जानती थीं। मगर चंद कांग्रेसियों ने ही उन्हें कुछ करने नहीं दिया।

राहुल को इन सब चीजों का थोड़ा अध्ययन करना होगा। 2004 से पहले का भी कि कैसे कांग्रेसी निराश थे। मगर सोनिया गांधी गांव-गांव घूमीं। अनथक मेहनत की। किसी को यकीन नहीं था। न वाजपेयी को अपनी हार का न कांग्रेसियों को अपनी जीत का। मगर सोनिया ने पासा पलट दिया। सरकार लाकर कांग्रेसियों के हाथ में रख दी। सब हतप्रभ थे। उस दौर की बातें राहुल को काफी याद होंगी मगर कभी भाजपा के नेताओं से बात हो तो उनसे पूछना चाहिए। प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज तो रहे नहीं मगर अभी भी कई भाजपा नेता हैं जो व्यक्तिगत बातचीत में दिल खोलकर बात करते हैं। वे राहुल को उनकी मां सोनिया गांधी की कड़ी मेहनत के बारे उसी तरह बताएंगे, जैसे वाजपेयी ने लोकसभा में इन्दिरा जी को उनके बेटे संजय गांधी के बारे बताया था।

1980 का चुनाव भारी बहुमत से जीतने के बाद लोकसभा में संजय गांधी का पहला भाषण था। युवा संजय ने जनता पार्टी के बखिए उधेड़ दिए। सामने विपक्ष की बैंच पर बैठे वाजपेयी जी को भी नहीं बख्शा। कड़े हमले किए। वाजपेयी जवाब देने खड़े हुए। सबकी आंखें उन पर जम गईं। वाजपेयी की भाषण कला को कौन नहीं जानता था। वाजपेयीजी ने प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी की तरफ देखा। कहा बधाई हो। इस युवा को सबसे ज्यादा जिसकी मेहनत से आप आज फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी हैं। सदन टेबल थपथपाने की जोरदार आवाजों से गूंज गया। राहुल को उसी तरह शायद कोई बताए कि 2004 की जीत का सारा श्रेय उनकी मां सोनिया गांधी को है। जिसे बाद में कांग्रेसियों ने गंवा दिया। और कुछ हद तक इसमें राहुल का अनिश्चय भी जिम्मेदार है।

राहुल ने 2004 में सांसद बनने के बाद महासचिव बनने में बहुत समय लिया। फिर अध्यक्ष बनने में और ज्यादा। मगर अध्यक्ष पद छोड़ने में बिल्कुल नहीं। राजनीति इतनी अनिश्चितता के साथ नहीं की जा सकती। कप्तानी तो बिल्कुल नहीं। और राहुल को यह बात समझना चाहिए की टीम में उनका रोल कप्तान का है। अब उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वे अध्यक्ष बनेंगे।

मीडिया और भाजपा बार-बार यह सवाल उठाता है कि मोदी का विकल्प क्या। इस सवाल में वह अप्रत्यक्ष रूप से यह मानता है कि विकल्प हो तो सोचा जा सकता है। यहां कांग्रेस को जोर देकर कहना चाहिए। राहुल गांधी। यह सही है कि एक बार फिर राहुल के खिलाफ चरित्रहनन अभियान पूरी तेजी से शुरू हो जाएगा। मगर वैसे भी कौन सा रुका हुआ है, या कम है।

राहुल को कमान अपने हाथ में लेना होगी। और सीखना यह होगा कि पार्टी या सरकार मजबूती से ही चलती है। चाहे वे इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के इन सात सालों को देख सकते हैं या अपनी दादी इन्दिरा गांधी के कड़े फैसलों के बारे में पढ़ और उस समय के बचे कुछ लोगों से जान सकते हैं। मोदी के फैसले से असहमत होना और विरोध करना अलग बात है, मगर राहुल को देखना यह चाहिए कि उन्होंने जो चाहा वह किया।

जाहिर है कि राहुल बिल्कुल अलग चीजें चाहेंगे। मगर जो भी चाहें, उन्हें कड़ाई से लागू करना होगा। पार्टी के अंदर और बाहर के विरोधियों की तरफ से उसी तरह बेपरवाह रहते हुए जैसे इन्दिरा गांधी रहती थीं और मोदी रह रहे हैं। सोनिया अन्ना और रामदेव के आंदोलनों की हकीकत जानती थीं। मगर चंद कांग्रेसियों ने ही उन्हें कुछ करने नहीं दिया। डरा कर रखा। हिम्मत से मजबूत फैसला नहीं लेने दिया। नहीं तो 2014 की कहानी कुछ और भी हो सकती थी।

जरूरी है, तम्बाकू के अवैध व्यापार पर नकेल

■ शोभा शुक्ला और बॉबी रमाकांत

तम्बाकू-जनित महामारियों से पूर्ण रूप से बचाव मुमकिन है, क्योंकि यह मानव निर्मित आपदा है। उद्योग अपने मुनाफे के लिए इस जानलेवा उत्पाद के व्यापार को बढ़ा रहे हैं, बदले में जनता की पूंजी और जान जा रही है और सरकारों के सतत विकास के प्रयास भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं।

'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, जो लाभ तम्बाकू नियंत्रण नीतियों के अनुपालन से मिलता है वह अवैध तम्बाकू व्यापार से खतरे में पड़ जाता है और सरकारों को राजस्व का भी नुक्सान होता है। सस्ते अवैध तम्बाकू उत्पाद से तम्बाकू-जनित महामारी अधिक पनपती है और तम्बाकू नियंत्रण नीतियों और कानून का भी उल्लंघन होता है। 'डब्ल्यूएचओ' के अनुसार अवैध व्यापार से अंतरराष्ट्रीय अपराधिक गतिविधियां भी पोषित होती हैं।

तम्बाकू का अवैध व्यापार एक वैश्विक समस्या है, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इससे निबटना जरूरी है। दुनिया के 180 से अधिक देशों ने 2012 में 'वैश्विक तम्बाकू नियंत्रण संधि' ('डब्ल्यूएचओ' फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टुबैको कण्ट्रोल) को पारित किया है। कानूनी रूप से बाध्यकारी यह संधि 2018 से लागू की गई। इस संधि को 62 देश पारित कर चुके हैं जिनमें भारत भी शामिल है। इस संधि की धारा-15 सरकारों को ताकत देती है कि वे आपस में मिलकर तम्बाकू के अवैध व्यापार पर अंकुश लगा सकें।

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के डॉ. एमजी वलावन के अनुसार, सरकार ने 2018 में अवैध तम्बाकू व्यापार के उन्मूलन के लिए वैश्विक संधि को पारित किया है और तब से इस दिशा में कुछ कार्य भी हुआ है। डॉ. वलावन ने कहा कि 'डब्ल्यूएचओ' के अनुसार, भारत में अवैध तम्बाकू व्यापार कुल सिगरेट खपत का छह प्रतिशत है, पर उद्योग इस आंकड़े को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। भारत में अवैध सिगरेट का विक्रय मूल्य 75.3 करोड़ डॉलर है और सरकार को इससे 39 करोड़ डॉलर के राजस्व का नुकसान होता है। डॉ. वलावन ने बताया कि भारत सरकार केन्या देश के मॉडल को अपने परिवेश में संशोधित कर अपना रही है जिसमें अवैध व्यापार के उन्मूलन के लिए हो रहे सभी कार्यों की कीमत उद्योगों को ही चुकानी पड़ेगी।

> कोविड-19 होने पर गंभीर परिणाम और मृत्यु होने की सम्भावना उन रोगों से बढ़ जाती है जिसका जनक तम्बाकू है- हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज, श्वास सम्बन्धी रोग आदि। तम्बाकू उद्योग को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराना जरूरी है जिससे तम्बाकू से होने वाले मानव शरीर और पृथ्वी पर सभी नुकसानों की पूरी भरपाई करने के लिए तम्बाकू उद्योगों को विवश किया जा सके।

तम्बाकू-रहित विश्व के लिए समर्पित 'स्मोक-फ्री पार्टनरशिप' से जुड़े लुक जूस्सेन के मुताबिक कोविड-19 महामारी के कारण, 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 4.4 प्रतिशत सिकुड़ गई है जिसके कारण अनेक देश आर्थिक मंदी का शिकार हो रहे हैं। यदि सरकारें अवैध तम्बाकू व्यापार पर अंकुश लगाएंगी तो राजस्व में तो वृद्धि होगी ही और जन स्वास्थ्य का लाभ भी मिलेगा। लुक जूस्सेन ने बताया कि हर साल अवैध तम्बाकू व्यापार से सरकारों को 40.5 अरब डॉलर के राजस्व का नुकसान होता है और यदि अवैध तम्बाकू व्यापार का अंत हो जाए तो सरकारें कम-से-कम 21 अरब डालर का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त कर सकेंगी।

लुक जूस्सेन ने चेताया है कि तम्बाकू उद्योग अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य नीतियों में हस्तक्षेप करता रहा है। अवैध तम्बाकू व्यापार के मुद्दे पर भी तम्बाकू उद्योग ऐसा तंत्र सुझाता है जिसका नियंत्रण उसके पास रहे। 'वैश्विक तम्बाकू नियंत्रण संधि' में सरकारों ने इसीलिए धारा-5.3 को पारित किया, जिससे कि स्वास्थ्य नीति में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। जिन सरकारों ने अवैध तम्बाकू व्यापार को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए वैश्विक संधि को पारित किया है, उनका वादा है कि सितम्बर 2023 तक वह ऐसी प्रभावकारी प्रणाली सक्रिय कर लेंगी।

दक्षिण-अफ्रीका की 'यूनिवर्सिटी ऑफ केपटाउन' की डॉ. हैना रोस का कहना है कि उनके देश में अवैध तम्बाकू व्यापार की समस्या तो जटिल है और सरकार ने अभी तक वैश्विक संधि को पारित भी नहीं किया है, लेकिन वहां तम्बाकू नियंत्रण और अवैध तम्बाकू व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावकारी कदम उठाये गए हैं।

कोविड-19 महामारी में जब तालाबंदी लगी तो दक्षिण-अफ्रीका में पांच महीने तक तम्बाकू विक्रय पर प्रतिबन्ध लग गया था जो अन्य देशों की तुलना में, बहुत लम्बी अवधि रही। भारत में तालाबंदी के दौरान सिर्फ छह हफ्ते तम्बाकू विक्रय प्रतिबंधित रहा था और बोत्सवाना में 12 हफ्ते। परन्तु दक्षिण-अफ्रीका में लम्बी अवधि के लिए तम्बाकू विक्रय पर प्रतिबन्ध का असर कम रहा, क्योंकि अवैध व्यापार के जरिये सिगरेट बिक रही थी। ऐसा अनुमान है कि वहां एक-तिहाई तम्बाकू व्यापार अवैध है।

डॉ. हैना रोस के शोध से ज्ञात हुआ कि तालाबंदी में नौ प्रतिशत लोग तम्बाकू सेवन को त्याग चुके थे और इनमें से दो-तिहाई, तालाबंदी और तम्बाकू विक्रय पर प्रतिबन्ध हटने के बाद भी तम्बाकू सेवन आरंभ नहीं कर रहे थे। चिंताजनक तथ्य यह है कि 93 प्रतिशत लोग तालाबंदी के दौरान तम्बाकू विक्रय पर प्रतिबन्ध के बावजूद अवैध तम्बाकू को खरीद रहे थे। अवैध सिगरेट की औसतन कीमत भी 250 प्रतिशत बढ़ गई थी।

डॉ. हैना रोस के मुताबिक दक्षिण-अफ्रीका में तालाबंदी के दौरान तम्बाकू विक्रय तो प्रतिबंधित रहा पर निर्यात के लिए तम्बाकू उत्पाद बनाने पर प्रतिबन्ध नहीं था। आंकड़े बताते हैं कि तालाबंदी के दौरान तम्बाकू निर्यात काफी बढ़ गया था, पर सिगरेट या तो देश के बाहर गई ही नहीं या बाहर जाकर वापस आ गई, जिससे कि अवैध रूप से बिक सके। डॉ. हैना रोस की मांग है कि दक्षिण-अफ्रीका सरकार, अवैध व्यापार का अंत करने के लिए वैश्विक संधि को पारित करे और तम्बाकू उत्पाद पर कर को अनेक गुणा बढ़ाए।

'वैश्विक तम्बाकू नियंत्रण संधि' के सचिवालय से जुड़े रोड्रिगो सैंटोस फिजो ने कहा कि अवैध तम्बाकू व्यापार के पूर्ण अंत से न सिर्फ जनस्वास्थ्य को लाभ मिलेगा बल्कि सरकारें राजस्व भी अधिक पाएंगी और सतत विकास के लिए अधिक गति से कार्य कर सकेंगी।

कोविड-19 होने पर गंभीर परिणाम और मृत्यु होने की सम्भावना उन रोगों से बढ़ जाती है जिसका जनक तम्बाकू है- हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज, श्वास सम्बन्धी रोग आदि। तम्बाकू उद्योग को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराना जरूरी है जिससे तम्बाकू से होने वाले मानव शरीर और पृथ्वी पर सभी नुकसानों की पूरी भरपाई करने के लिए तम्बाकू उद्योगों को विवश किया जा सके।

डॉ. तारासिंह बाम, जो 'इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग डिजीज' के एशिया-पैसिफिक निदेशक हैं, कहते हैं कि मानव निर्मित तम्बाकू महामारी का पूर्ण रूप से अंत आवश्यक है, क्योंकि इससे पूर्ण रूप से बचाव मुमकिन है। इसके धंधे से जितना राजस्व आता है, उससे कई गुणा अधिक नुकसान होता है और लाखों लोग तम्बाकू सेवन से मरते हैं। हर साल विश्व में 80 लाख से अधिक लोग तम्बाकू से मारे जाते हैं। तम्बाकू के व्यापार पर पूर्ण रोक लगाना जरूरी है, पर हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि तम्बाकू, अवैध हो या वैध, हर रूप में घातक है।

पावन प्रसंग

आपत्तियों का सामना धैर्य एवं साहस के साथ करें

आपत्तियां एवं कठिनाइयां जीवन का स्वाभाविक अंग हैं, जो धूप-छांह एवं दिन-रात की भांति हमारे जीवन में आती-जाती रहती हैं, लेकिन जब वे आती हैं तो हम इसका सामना कैसे करते हैं, इनसे कैसे निपटते हैं, इनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या रहती है- इसके आधार पर हमारे जीवन की दशा-दिशा निर्धारित होती है। यदि हम एक सजग जिज्ञासु की भांति धैर्य एवं साहस के साथ इनका सामना करते हैं, इनसे आवश्यक सबक लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो जीवन के वे विकट पल हमें जीवन जीने की कला का महत्वपूर्ण शिक्षा देकर जाते हैं अन्यथा वे हमें तोड़कर, जीवन में कटुता का समावेश कर, अस्तित्व के तार को और उलझाकर जाते हैं।

सामान्य क्रम में आपत्तियों के आने पर व्यक्ति घबरा जाते हैं, उसके हाथ-पैर फूल जाते हैं। लगता है कि भगवान ने हमारे ऊपर यह कैसी बिजली गिरा डाली। व्यक्ति अपना होश खो बेठता है, किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है और इनसे बचने का, इनको टालने का यथासंभव प्रयास करता है, लेकिन जब ये चली जाती हैं और इनका समय बीत जाता है तो फिर इन्हीं को याद कर व्यक्ति हँसता है। इनकी कथा-गाथाओं को व अपने साहस के किस्सों को बड़े मनोरंजन के साथ आनंद लेते हुए अपने मित्र, दोस्तों, नाती-पोतों के बीच में सुनाता है।

वास्तव में कठिनाइयों एवं आपत्तियों के प्रति हमें हमारी सोच बदलने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में कठिनाइयां हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आती हैं। वे हमारा प्रारब्ध हैं और हमारे संचित कर्मों का बोझ हलका कर हमारे जीवन को और बेहतर बनाती हैं। इसके साथ हमारे संचित पापों का भार हलका होने के साथ हमारी अंत:चेतना शुद्ध एवं निर्मल हो जाती हैं, इसके साथ डी हमारी अंत:शक्तियों का जागरण भी होता है। कठिन समय इनको झकझोर कर हमारी उन्नति में ये सहायक बनते हैं। इस तरह ये एक तरह से ईश्वर की ओर से उपहारस्वरूप होती है, जो हमारी बेहोशी, अज्ञानता, आलस्य, अहंकार, जड़ता और व्यामोह को नष्ट करने आती हैं।

इस तरह आपत्तियों से चिंतित न हों तथा प्रत्येक परिस्थिति में आगे बढ़ते रहें। अपने धैर्य को स्थिर रखते हुए सजगता, बुद्धिमता, शांति और दूरदर्शिता के साथ कठिनाइयों से पार निकलने का प्रयास करें। आप पाएंगे कि हर विषम परिस्थिति के बाद हम अधिक निखार के साथ, अधिक सशक्त बनकर बाहर निकल रहे हैं। बुरे दिन तो निकल जाएंगे लेकिन साथ ही वे अनेकों अनुभव, सद्गुण, सहनशक्ति एवं सूझ का वरदान देकर जाएंगे। हम जिन महापुरुषों को आज प्रेरणास्रोत के रूप में देखते हैं, अनुकरणीय मानते हैं, वे कठिनाइयों की पाठशाला में उत्तीर्ण होकर ही इसके अधिकारी बन सके हैं। वे दुख, कष्ट, आपत्ति एवं प्रतिकूलता की भट्ठी में तपकर ही कुंदन बनकर निखरे और अपनी आभा के साथ युग को प्रदीप्त कर गए। जिसका जीवन जितना अधिक सुख-सुविधाओं एवं अनुकूलताओं की गोद में पला-बढ़ा, उसकी नैसर्गिक, क्षमताएं उतनी ही प्रसुप्त रह गईं और उनका जीवन उतना ही हलके में निकल गया, जबकि विपत्तियों की प्रयोगशाला में ही महान व्यक्तियों का विकास होता है, जिनका वे सहर्षता से वरण करते हैं।

कितनी ही उच्च आत्माएं, तपरूपी कष्ट को अपना परम मित्र और विश्वकल्याण का मूल समझकर उसे स्वेच्छापूर्वक हृदय से लगाती हैं। वे दुखों के आने पर अधीर नहीं होते और उन्हें प्रारब्ध कर्मों का बोझ समझ कर प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हैं। विकट समय निकल जाता है, लेकिन तप की अग्नि से प्रदीप्त इनका कालजयी व्यक्तित्व युग-प्रवर्तकों तथा संघर्षशील व्यक्तियों के लिए प्रेरक शक्ति का काम करता है।

अखंड ज्योति

आपके पत्र

पत्रकारिता का लक्ष्य लोकतंत्र और लोकतंत्रगामी को उन्नत बनाना

अखबारी दुनिया में प्रतिदिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरे और दबाव की चर्चा होती है। पत्रकारिता के स्वरूप को लोकतंत्रगामी बनाने की भी बहुत बहस होती है। पत्रकार कई प्रकार के खतरों का रोना तो रोते हैं, लेकिन इसके मुक्ति के मार्ग पर विचार नहीं करते। पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति और इस पर बाजारीकरण के बढ़ते प्रभाव से सभी अनभिज्ञ हैं। सदियों से व्यक्ति, विचार, साधन और पूंजी में वर्चस्व की जंग चल रही है। पत्रकारिता में यदि मुनाफा ही ईश्वर हो जाएगा तो समाज में विकृति को रोका नहीं जा सकता है। पत्रकार अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों तक समाचार पहुंचाते हैं। हथियार जब सिपाही के हाथ में होता है तो वह सुरक्षा के लिए उपयोग होता है। किसी डकैत के हाथ में जब हथियार आ जाता है तो वह सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है। हथियार नहीं हाथों का ही महत्व है। जहां तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है, इसको सबसे अधिक खतरा सरकारों का होता है। यह पत्रकारिता की प्रासंगिकता है कि किसी भी विकट से विकट परिस्थितियों में भी अखबार को निकालने की पूरी कोशिश रहती है। लोकतांत्रिक समाज में पत्रकारिता को चौथा स्तम्भ माना जाता है। बिना किसी खास संवैधानिक अधिकारों और खासकर भारत जैसे देशों में सतत आर्थिक सुरक्षा के बावजूद अगर सच की आंख से किसी घटना को देखना संभव है तो उसका बड़ा और भरोसेमंद जरिया पत्रकारिता ही है। इस लिहाज से देखें तो पत्रकार को समाज का संरक्षण हासिल होना चाहिए। पत्रकारों का हित संघर्ष की प्रतिबद्धता सूची में निचले पायदान पर चला गया है। केंद्र और राज्य सरकारों को यह सोचना चाहिए कि अपने खतरों की परवाह किये बिना रात-रात जाग कर अखबार निकालना और लोगों के उठने के पूर्व अखबार पाठकों के दहलीज पर पहुंचाना यह संघर्ष निरन्तर चलता ही रहता है। लोग रविवार को भी आराम करते हैं और पत्रकार रविवार को भी समाचार की खोज में घर से बाहर रहता है। यह हमेशा डर बना रहता है कि कोई मुख्य समाचार दूसरे अखबार में छप जाए और हमारे से छपना बाकी न रह जाए। देश में आम आदमी को सरकार की तरफ से सहूलियत दी जाती रही है, लेकिन पत्रकार तो देश की सेवा करने के लिए आते हैं। उनको किसी से गिला शिकवा नहीं है। पत्रकारों पर जानलेवा हमले होते हैं, लेकिन सरकारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आखिर देश की सेवा करते हुए सिपाही शहीद होते हैं तो उनके परिवार को मरणोपरांत याद किया जाता है। वो बंदूक के सिपाही हैं और पत्रकार कलम का सिपाही। कोरोना महामारी में सेवा देते हुए सैकड़ों पत्रकार ने अपनी जान गंवाई है। भारत में बढ़ते खतरों को लेकर अध्ययन की परिपाटी टूट गई है। पहले पत्रकारों का संगठन हुआ करते थे लेकिन ठेकेदारी की प्रथा के विकसित होने के बाद पत्रकारिता की दुनिया में संगठन नाम मात्र के रह गए हैं। पत्रकारिता के बदलाव का माध्यम और जनता की आवाज बनने की कोशिश हमेशा पत्रकार के मन में रहती है। हम पत्रकारिता को हर समय लोकतंत्रगामी बनाने का लक्ष्य रख कर आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में अखबार और टेलीविजन पर प्रसार और विज्ञापन की कमी के कारण नकारात्मकता बढ़ी है। बाजार में प्रतिस्पर्धा भी कम नहीं है। अखबार से जुड़े रहने वाले पत्रकार कई घटनाओं के साक्षी रहे हैं लेकिन वो घटना सपने की तरह भूल कर आगे बढ़ते रहते हैं। कभी-कभी शासन प्रशासन का दबाव भी झेलना पड़ता है। कई बार लालच भी दिए जाते हैं। लेकिन जो देशभक्त और लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने वाले पत्रकार लालच को दरकिनार करते हुए अपने उसूलों से समझौता नहीं करते हैं। पत्रकारिता को सांसद और मंत्री की सीढ़ी बनाने के बजाय हर पत्रकार को अपने जीवन का लक्ष्य पत्रकारिता को लोकतंत्रगामी और लोकतंत्र को उन्नत बनाने का होना चाहिए। जो पत्रकार अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने के सपने देख रहे हैं पैसे कमाने के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं तो यह गलत है। पैसे कमाने हैं तो बिजनेस में जाइये। यहां तो देशप्रेम, देशभक्ति और जनता की सेवा ही मुख्य लक्ष्य होता है।

कांतिलाल मांडोत, सूरत

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय : फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in